

प्रेषक,

संख्या : 36-सं(2)/XXXVI(1)/2007-08-1-सं(2)/07

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2

विषय:- कुटुम्ब न्यायालयों में संविदा के आधार पर तैनात वाहन चालक को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में धनराशि की स्वीकृति ।

देहरादून : दिनांक : 04 फरवरी 2008

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-109/यूएच०सी०/एडमिन-बी/कुटुम्ब न्यायालय/07, दिनांक 10.1.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 8-सं(2)/XXXVI(1)(2)/2007-1-सं(2)/07, दिनांक 31.7.2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुटुम्ब न्यायालयों में संविदा के आधार पर तैनात वाहन चालक को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में 42-अन्य व्यय से भुगतान किये के सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति एवं तदक्रम में 42-अन्य व्यय मद के सम्प्रति बजट में कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण तथा वर्तमान में आवश्यकता की दृष्टिगत संलग्न बी०एम०-15 के स्तम्भ-1 में अंकित मद संख्या-08-कार्यालय व्यय से अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचती से बी०एम०-15 के स्तम्भ-5 में अंकित मद संख्या-42-अन्य व्यय में रुपये 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यवर्तित कर व्यय करने की महानिबन्धन राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) प्रत्येक माह होने वाले व्यय की सूचना प्रपत्र बी०एम०-13 में अंकित कर उपलब्ध कराया जाय ।
- (ii) उक्त धनराशि बजट मैनुअल के सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(iii) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आधोऽन्तर्गत-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-04-पारिवारिक न्यायालय-00-42-अन्य व्यय" से किया जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकिय संख्या यू०ओ० 1275/XXVII(5)/2008, दिनांक 29.1.08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक : बी०एम०-15

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 36-सं(2)/XXXVI(1)/2007-08-1-सं(2)/07-तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदार), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 3- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 4- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

पुनर्विनियोग 2007-2008 आयोजनेत्तर

नियंत्रक अधिकारी का नाम - महानिदेशक, मा० उत्तराखण्ड राज्य न्यायालय, पुर्तावाली, नीनीताल ।

नियंत्रक अधिकारी का नाम- महानिदेशक, भा० उत्तराखण्ड राज्य न्यायालय,
प्रशासनिक विभाग का नाम- न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

वजेट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक प्रवृत्त अथवा अन्य विवरण	वजेट वर्ष की अनुमानित व्यय	अवशेष (सन्तुल्य) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्वामन्त्रित की जाती है।	पूर्णविवरण के बाद लेखा-5 की कुल धनराशि	पूर्णविवरण के बाद लेखा-5 की कुल धनराशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनोत्तर-105-शिविल एवं सेशन्स न्यायालय-04-पारिवारिक न्यायालय-00-08-कार्यालय व्यय	91	109	250	2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनोत्तर-105-शिविल एवं सेशन्स न्यायालय-04-पारिवारिक न्यायालय-00-42-अन्य व्यय	159	300	क-व्यय होने के कारण । ख- प्रालिभान कम एवं आवश्यकता अधिक होने के कारण ।
प्रयोजित किया जाता है कि पूर्णविवरण में बजेट वर्ष 2014-15 के परिच्छेद 150-156 में उल्लिखित धनराशि में एवं शेष में	91	109	250	150	159	300	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनिर्माण में बहुत संयुक्त के पीछे 150-156 में उल्लिखित प्रतिभाग एवं सीमाओं का उल्लेख नहीं किया गया है ।	150	159
--	-----	-----

LEHLE 20FHD2002

from 1997

5107-1275-6/107 37407-5/2008

देहरादून : दिनांक : 29 जनवरी, 2008

संख्या ७६

महालेखाकार (लंछा एवं मुकदारी)

उत्ताखण्ड, औद्योगिक विकास गंठ.

भाजस, देशादून ।

संख्या-३६ सं(२)/XXXXVI(१)/२००७-०९-१ सं(२)/०७-सद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

१-०० महानिबन्धक, भा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय मैनीताल ।

2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

3-
यदिष्ट कोषाधिकारी नैनीताल ।

4-
द्वितीया अनुभाग-५ उत्तराखण्ड शासन ।

— १६ —

एन०एच०एच०एच०

अपर सचिव, दिल्ली ।

आता ही,

(आलोक्य कुमार वर्मा)

આપનું શાંતિથી